SLMs are being set up in all the States/UTs to implement the literacy programmes.

(iv) Involvement of Panchayati Raj Institutions in the literacy programmes and sensitization of Panchayati Raj representatives.

(v) Launching of 'Operational Restoration' in those districts which have not been able to achieve desired objectives.

(vi) Opening of special cells in NLM for monitoring the literacy campaigns in four major Hindi-speaking States.

Illiteracy rate based on the 1991 Census

S.No.	States/UT	Illiteracy Rate (%)
1.	Andhra Pradesh	55.91
2.	Arunachal Pradesh	58.41
3.	Assam	47.11
4.	Bihar	61.52
5.	Delhi	24.72
6.	Goa	24.49
7.	Gujarat	38.71
8.	Haryana	44.15
9.	Himachal Pradesh	36.14
10.	Karnataka	43.96
11.	Kerala	10.19
12.	Madhya Pradesh	55.80
13.	Maharashtra	35.13
14.	Manipur	40.11
15.	Meghalaya	50.90
16.	Mizoram	17.73
17.	Nagaland	38.35
18.	Orissa	50.91
19.	Punjab	41.49
20.	Rajasthan	61.45
21.	Sikkim	43.06
22.	Tamil Nadu	37.34
23.	Tripura	39.56
24.	Uttar Pradesh	58.40
25.	West Bengal	42.30
26.	A&N Islands	26.98
27.	Chandigarh	22.19
28.	D&N Haveli	59.29
29.	Daman & Diu	28.80
30.	Lakshadweep	18.22
31.	Pondicherry	25.26

Figures of Jammu & Kashmir not available as no census was held there.

गुजरात में प्रदूषण

899. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में बडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, अहमदाबाद और सूरत के पर्यावरण में सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन-डाइआक्साइड और कार्बन डाइआक्साइड जैसी गैसों का जमाव कितनी मात्रा में है;

(ख) इन शहरों में वायु-प्रदूषण से बचाव के लिए सुरक्षा स्तरों के निर्धारण हेतु क्या प्रणाली अपनायी जा रही है;

(ग) तेल, रसायनों और उर्वरकों तथा खाण्डसारी के उत्पादन में लगी फैक्टरियों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों का उक्त प्रदूषकों में कितना योगदान है तथा ऐसी फैक्टरियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त फैक्टरियों से इस हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी अपनाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (घ) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अहमदाबाद, व बडोदरा, सूरत तथा भरूच (अंकलेश्वर) के लिए सल्फर डाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन आक्साइड जैसी गैसों का परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तर, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उनके निर्धारित मानकों से कम है (120 माइक्रोग्राम प्रति सामान्य घन मीटर)।

1995 के दौरान पाये गये परिवेशी वायु गुणवत्ता के स्तर निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	शहर	सल्फर डाइआक्साइड का संकेन्द्रण	नाइट्रोजन आक्साइडों का संकेन्द्रण*
1.	अहमदाबाद	17-85	19-26
2.	बड़ोदरा	60-75	17-20
3.	सूरत	75-101	24-33
4.	भरूच (अंकलेश्वर)	89-96	20-30

*माइक्रोग्राम प्रति सामान्य घन मीटर

परिवेशी वायु में कार्बन डाइआक्साइड के संकेन्द्रण की मानीटरन नहीं की जा रही है। प्रमुख उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित कर लिए गए हैं। उद्योगों के

लिए प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय करके निर्धारित मानकों का पालन करना अपेक्षित होता है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् 333 चूक इकाईयों के विरूद्ध कार्रवाई की है।

Construction and Electrification of Odagaon-Banda Munda and Barsuan Rail Line

900. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the 138 Km. Odagaon-Banda Munda and Barsuan rail line has been constructed;

(b) if so, the steps taken for electrification of that line; and

(c) the target date set for the completion of the electrification work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) While rail line exists between Bondamunda and Barsuan, there is no line connecting Odagaon.

(b) Bondamunda-Barsuan is a part of Bokaro Steel City-Bondamunda-Barsuan/ Kiriburu Project where electrification work has been takenup and targetted for completion by March, 1998.

Central Outlay for Agricultural Development in Punjab

901. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the Central outlay for agricultural development during the year 1996-97 in the country particularly in Punjab;

(b) whether it is a fact that our country is earning huge amount from agricultural sector; and

(c) if so, the steps being taken by Government to solve the storage problem of foodgrains?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The Central Plan outlay for agricultural development during 1996-97 is Rs. 1487 Crores. Funds are released to the States on the basis of proposals received and progress of expenditure under various Plan schemes. Till October, 1996, an amount of Rs. 140 crores has been released to Government of Punjab.

(b) As per estimate prepared by the Central Statistical Organisation, the Gross Domestic Product (GDP) accrued on account of agriculture during 1994-95 was Rs. 68851 crores as against the total GDP of Rs. 251010 crores, which is about 27.4%.

(c) As per information furnished by Department of Food, the total covered and plinth (CAP) storage area capacity with Food Corporation of India is at present 249.25 lakh tonnes with a per cent utilisation of 60%. At macro level, the existing storage capacity is adequate to store the available stocks. Additional storage capacity is hired by local field officers in case of need from Central Warehousing Corporation/State Warehousing Corporations/private parties, etc.

खनन हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी

902. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस बात की जानकारी है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1970 के अधिनियमन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में खानों के अनेक पट्टा समझौते किये गये हैं या उनका नवीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकार की सिफारिशों पर दी गई स्वीकृति पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की गयी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या-क्या उपयुक्त कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां,।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंत्रालय द्वारा जारी नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अलग से और एक ही समय में ली जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।